अमृत विचार

बरेली महानगर

www.amritvichar.com

बरेली , सोमवार,2 फरवरी 2026

सुविचार

जीवन में अनेक विफलताएं केवल इसलिए होती हैं क्योंकि लोगों को यह आभास नहीं होता है कि जब उन्होंने प्रयास बन्द कर दिए तो उस समय वह सफलता के कितने क़रीब थे। - थोमस एडिसन

बरेली के प्रमुख समाचार

- राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना हमारा दायित्व-II
- बजट नए भारत की कल्पना को साकार करने वाला : दुर्विजय-III
- बजट से छोटे करदाताओं को राहत-IV

बजट पर महिलाएं बोलीं

इस बार बजट में विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को मात्र ऋण लेने वाली नहीं, अपने बिजनेस की स्वामिनी बनाने का प्रावधान किया है। इसके फलस्वरूप उन्हें स्थायी बाजार, आय और नेतृत्व का अवसर भी प्राप्त हो जायेगा, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। वित्तमंत्री ने महिलाओं को ''शी मार्ट्स'' का तोहफा देकर उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का पूरी तरह से मालिक बना दिया है। विशेष बात यह है कि वे अपने उत्पादों को सीधे बेच भी सकेंगी। हम सभी महिलाओं को उनका एवं अपनी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए।

-डॉ. शिफालिका, प्रोफेसर

सरकार ने महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय से जोड़ने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं, लेकिन, बजट में सब्जी, तेल और चावल जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। - **मानसी**, सुभाष नगर ।

सभी योजनाएं अच्छी तो हैं, लेकिन बजट से कहीं भी महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही है। घरेलू खर्च में लगने वाले पैसे और कम हो जाते तो राहत होती। इसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए।

- **सीमा अरोड़ा**, अवधपुरी कालोनी।

बजट के बाद बाजार की स्थिति निराशाजनक रही क्योंकि एसटीटी में वृद्धि से ट्रेडिंग लागत बढ़ने से बाजार में बेचैनी बढ़ी। इसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट आई और बाजार लाल रंग में बंद हुआ। **-हेमा खटवानी**- शेयर्स का कारोबार

विकास की राह पर बजट... लेकिन कई अपेक्षाएं रहीं अधूरी

टैक्स चोरी पर सजा की जगह जुर्माना देने की घोषणा को सभी वर्गों ने स्वागत योग्य बताया, तमाम पहलुओं पर विश्लेषण

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट 2026 पेश किया, जिसे लेकर सुबह से ही घरों, दुकानों, शोरूम, होटलों और गली-मोहल्लों की दुकानों पर लोग टीवी स्क्रीन से बजट की हर घोषणा पर नजर बनाए हुए थे। शहर के उद्यमी, व्यापारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बजट के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर रहे थे। कर कटौती, निवेश प्रोत्साहन, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं औरआर्थिक सुधारों पर चर्चा गर्म रही।

बजट को लेकर व्यापारियों का कहना है कि छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए कोई राहत नहीं दी गई, जबकि आम लोगों को आयकर में अधिकतम 20 प्रतिशत

सिविल लाइंस स्थित एक शोरूम पर बजट का सीधा प्रसारण देखते लोग। ● अमृत विचार

- **व्यापारियों से लेकर उद्यमियों और आमजन की सुबह से टिकी रहीं टीवी स्क्रीन पर नजरें**
- **आयकर में राहत नहीं मिलने पर नाराजगी तो कई चीजों में बजट मिलने पर की सराहाना**

जरी जरदोजी पर कोई घोषणा न होने से मायूसी

आम बजट में कपड़ा उद्योग को लेकर कई घोषणा की गई हैं, पर जिले की पहचान जरी जरदोजी को अछूता रखा गया है। इससे कारीगरों को मायूसी हाथ लगी है। जिले में शहर से लेकर देहात तक कारखानों में बड़ी संख्या में लोग जरी जरदोजी का काम करते हैं। कुछ समय से जरी जरदोजी का कारोबार ठप हो गया है। जरी जरदोजी को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। फिर भी इसके दिन नहीं बदल सके हैं। कारोबारी महेश बताते हैं कि आम बजट में जरी जरदोजी को लेकर काफी उम्मीदें थी। सरकार ने कपड़ा उद्योग पर तो ध्यान दिया पर जरी जरदोजी के कारोबार पर नहीं। इससे जिले के लाखों लोगों में काफी हताशा है।

तक छूट की उम्मीद थी। आयकर स्लैब में कोई बदलाव न होना और पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कोई कमी न होना कई वर्गों को निराश कर गया। इसके अलावा दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा, कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ाने, जीएसटी रिटर्न और नोटिस प्रक्रिया को सरल बनाने, ऑनलाइन कारोबार पर निगरानी और कच्चे माल के सापेक्ष उत्पाद पर जीएसटी समायोजन जैसी उम्मीदें भी पूरी नहीं हुईं। कर चोरी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान स्वागत योग्य रहा, लेकिन उद्यमियों और आम लोगों की बड़ी अपेक्षाएं अधूरी रह गईं। बजट में कुछ सकारात्मक पहल भी हैं। उद्यमियों ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए दस हजार करोड़ रुपये का आवंटन उद्यमिता को बढ़ावा देगा और छोटे व्यवसायियों को विस्तार के अवसर देगा। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की दवाओं के दाम घटाने का कदम आम मरीजों के लिए राहत भरा बताया। वहीं, बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और रेल में रियायती टिकट पर कोई कदम न उठाना निराशाजनक रहा। चार्टर्ड अकाउंटेंटों का कहना है कि बजट ने कुछ क्षेत्रों में उम्मीदें पूरी की हैं, लेकिन कई वर्गों की आकांक्षाएं अभी भी अधूरी रह गई हैं।

अल्पसंख्यकों के हितों का बजट में ध्यान रखा गया : शहाबुद्दीन

बरेली, अमृत विचार : ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि केंद्रीय बजट स्वागत योग्य है, जिसमें समाज के हर तबके का ख्याल रखा गया है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए 3350 करोड़ का बजट दर्शाता है कि अल्पसंख्यकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मौलाना ने कहा कि बजट में व्यापार, उद्योग, बाजार, नौकरी पेशा, घरेलू, युवा, खेल, शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में अलग-अलग बजट देकर देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की गई है। बजट में प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की रेखाएं झलक रही हैं।

एमएसएमई को मजबूती देने वाला है बजट

आईआईए : पीलीभीत बाईपास रोड स्थित होटल में उद्यमियों ने देखा बजट का सजीव प्रसारण

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार : इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) बरेली चैप्टर के तत्वावधान में रविवार को पीलीभीत रोड स्थित होटल में केंद्रीय बजट 2026 का सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में उद्योग जगत से जुड़े उद्यमी, प्रतिनिधि और सदस्य शामिल हुए और केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं, नीतिगत सुधारों और उद्योग जगत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर विस्तृत परिचर्चा की। चर्चा के दौरान एमएसएमई, निवेश, स्टार्ट-अप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर विशेष रूप से मंथन किया गया।

परिचर्चा को संबोधित करते हुए आईआईए बरेली चैप्टर के चेयरमैन मयूर धीरवानी ने कहा कि केंद्रीय बजट अत्यंत अग्रगामी, संतुलित और उद्योग-हितैषी है। बजट में एमएसएमई को ''चैम्पियन'' के रूप में स्थापित करने की स्पष्ट मंशा दिखाई देती है, जिससे यह साबित होता है कि सरकार एमएसएमई सेक्टर को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए उसके सशक्तिकरण के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। कर प्रणाली को सरल बनाने और अनुपालन प्रक्रिया को आसान करने से उद्यमियों को वास्तविक रूप से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ मिलेगा।

पीलीभीत रोड पर स्थित होटल में बजट का सीधा प्रसारण देखते उद्यमी और आईआईए के पदाधिकारी। ● अमृत विचार

- **कार्यक्रम में ऋण सुविधा, क्रेडिट गारंटी व स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन पर भी हुई चर्चा**

चैप्टर सचिव रजत मेहरोत्रा ने बजट को उद्योग और उद्यमिता के लिए मजबूती देने वाला बताते हुए कहा कि ऋण सुविधा, क्रेडिट गारंटी, स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस से औद्योगिक विस्तार को गति मिलेगी। वहीं कोषाध्यक्ष श्री आशीष गुप्ता ने रोजगार सृजन, स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया से जुड़े प्रावधानों को लघु व मध्यम उद्योगों के लिए नई ऊर्जा देने वाला बताया। परिचर्चा के अंत में उपस्थित सभी सदस्यों ने एकमत होकर केन्द्रीय बजट 2026 की सराहना की और इसे उद्योग, व्यापार व देश की समग्र अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक दिशा में एक मजबूत कदम करार दिया।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक राजा कुमार, मुख्य शाखा प्रबंधक अमित उपाध्याय, प्रबंधक सौरभ, सलमान खान ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए संचालित विभिन्न ऋण और वित्तीय सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज गोयल, सीईसी. सदस्य विमल रिवाड़ी, राष्ट्रीय सचिव तनुज भसीन, एसके सिंह, मनोहर लाल धीरवानी, मनोज पंजाबी, धनंजय विक्रम सिंह, शेखर अग्रवाल, तेजेंद्र सिंह, तुषार गोयल, जितेंद्र सिंह, पीयूष अग्रवाल, डॉ. मनीश शर्मा, डॉ. रतन गंगवार, रवि अग्रवाल, राजीव आनंद, सुनीत मूना, अमन अरोड़ा, प्रियंक वर्मा, अशोक मित्तल, अजय शुक्ला, सलिल बंसल, शुभम अग्रवाल, अंकित बंसल समेत सभी लोगों ने बजट को बेहतर बताया।

बजट पर अलग-अगल संगठनों की प्रतिक्रिया

महिलाओं के लिए बजट में काफी कुछ दिया है। शी-मार्ट से विस्तार, जिलों में गर्ल्स हास्टल का निर्माण और महिलाओं के लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल टूल्स जैसे शी-मार्क बजट में शामिल किया जाना काफी अच्छी बात रही। जो महिलाएं स्टार्ट अप शुरू करने जा रही हैं या फिर कर रही हैं, उनके लिए बजट में बहुत कुछ है। महिला स्वावलंबन की दिशा में अच्छी पहल है। **-डॉ. दीक्षा सक्सेना**, अध्यक्ष सृजन वेलफेयर सोसाइटी

बजट में दस हजार करोड़ रुपये के आवंटन के साथ ''बायो फार्मा शक्ति'' योजना की घोषणा सराहनीय है। देश में इस वक्त डायबिटीज, कैंसर और ऑटो-इम्यून (बीमारियों से लड़ने की ताकत संबंधी बीमारियां) जैसी बीमारियों के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछली बार सरकार ने डे-केयर कैंसर सेंटर व कैंसर की 36 दवाइयां ड्यूटी फ्री की थीं। नकली दवा बनाने वालों पर सख्ती और दवाइयों के मूल्य नियंत्रण के प्रयास से आम जनता को लाभ होगा। **-मुहम्मद खालिद जीलानी**, (उपभोक्ता मामलों के वकील एवं आरटीआई एक्टिविस्ट)

स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बजट ऐतिहासिक है। पहली बार देश का हेल्थकेयर बजट 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। यह न सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से बड़ा है, बल्कि सरकार की उस सोच को भी दर्शाता है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को विकास की बुनियाद माना जा रहा है। देश में मजबूत, समावेशी और आधुनिक हेल्थकेयर सिस्टम तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ आयुष और पारंपरिक चिकित्सा पर फोकस किया गया है। जिला अस्पतालों की क्षमता में 50 प्रतिशत वृद्धि आमजन को बेहतर इलाज देने में सहयोगी होगी। **-डॉ. विनोद पागरानी**, सदस्य इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन

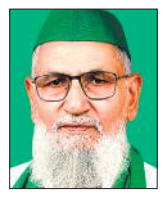

बजट में किसानों के स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीणों की अनदेखी की गयी। इस बजट से कोई लाभ किसानों को नहीं पहुंचेगा, यह बजट धनवानों के लिये है, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो पाएगी, किसानों के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। **हाजी एम. इकबाल एडवोकेट**, जिला प्रवक्ता भाकियू टिकैत

रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ने से करदाताओं को राहत

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार : आम बजट में टैक्स पेयर्स, व्यापारियों और आमजन के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आयकर रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ने से आईटीआर देने वालों को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीखों को अब श्रेणी के अनुसार संशोधित किया गया है। इसमें आईटीआर 1 और 2 (बिना ऑडिट वाले), इनके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। आईटीआर 3, 4, 5 और 7, इन फॉर्म्स को भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी।

टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत यह भी है कि अब वे अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज (संशोधित) कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए कुछ नॉमिनल फीस (नाममात्र शुल्क) देनी होगी। ऑडिट रिपोर्ट और मैनपावर सप्लाई पर नए नियम लागू किए हैं। यदि ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में 30 दिन की देरी होती है तो 75 हजार रुपये और उसके बाद 1.50 लाख की लेट फीस चुकानी होगी।

-सीए विनीश अरोड़ा, सचिव बरेली सीए एसोसिएशन

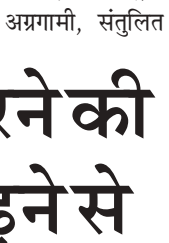

बजट में इनकम टैक्स स्लैब में नई राहत नहीं मिली, लेकिन पिछले बजट में दी गई कर छूट को जारी रखना एक सकारात्मक कदम है, लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए मध्यम वर्ग एवं सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त टैक्स राहत की अपेक्षा थी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई वृद्धि न किए जाने के कारण इस बढ़ी हुई आय का बड़ा हिस्सा टैक्स के दायरे में आ जाएगा, जिससे हाथ में आने वाली आय पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। वहीं, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स कानून से प्रक्रियाएं सरल होंगी, रिटर्न फाइलिंग अधिक सहज और करदाताओं के लिए अनुपालन आसान होगा, जो लंबे समय में सकारात्मक सुधार माना जा सकता है। **-सीए रजत कुमार बंसल**

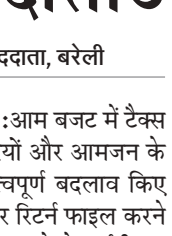

कपड़ा, चमड़ा, जूता आदि सस्ता होने से आमजन को लाभ मिलेगा। बाहर पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों पर भी टैक्स का बोझ कम होगा। हर लिहाज से बेहतर बजट है। बजट में सभी का ख्याल रखा गया है। इससे देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण को आभार। **-शानू काजमी**, व्यापारी

बजट में जो घोषणाएं होती हैं उनकी सच्चाई की समीक्षा जमीन पर भी होनी चाहिए, वैसे मेडिकल टूरिज्म हब बनाने का प्रस्ताव जनता, विदेशी पर्यटक और सरकार सभी को लाभ देगा। इस बार का बजट सभी वर्गों को लाभ पहुंचने वाला है। **-डॉ. प्रमेंद्र माहेश्वरी**, सचिव, सेंट्रल यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

सेवानिवृत कर्मियों व पेंशनरों की उपेक्षा

बरेली, अमृत विचार : सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी संजीव मेहरोत्रा का कहना है कि बजट में सेवानिवृत कर्मचारियों और पेंशनरों की पूरी उपेक्षा की गई। बैंक पेंशन अपडेशन पर कोई जिक्र नहीं है। कोविड काल में सीनियर सिटीजन से रेल किराये में छीन ली गई रियायत की सुविधा बहाल होने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं हुई। एक बड़ी मांग कि सीनियर सिटीजन को ग्रुप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी की छूट मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली।

केंद्रीय बजट में मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को बड़ा समर्थन

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार : इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने रविवार को आईआईए भवन लखनऊ में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा सत्र का आयोजन किया। इसमें आईआईए के पदाधिकारी, उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम में बताया गया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में सात प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार की गई है, साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास पर नए सिरे से जोर दिया गया है।

आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने बजट की सराहना करते हुए इसे 'भविष्योन्मुखी और विकास-संचालित' बताया। उन्होंने कहा कि बायोफार्मा, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और हाई-स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में आवंटन, साथ ही सूक्ष्म उद्योगों के लिए ग्रोथ फंड, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इको-सिस्टम को मजबूत करेंगे और सीधे एमएसएमई क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगे। यह भी बताया कि इक्विटी समर्थन, क्षेत्र-विशेष उपाय, टियर-2 और टियर-3 शहरों पर ध्यान और कॉर्पोरेट मित्र पहल जैसे कदम उत्साहजनक हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश अग्रवाल ने उच्च-प्रिसिजन उपकरणों के लिए उच्च-तकनीकी कार्यशालाओं की स्थापना और रेयर अर्थ मैग्नेट पर फोकस को सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने जलमार्गों और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुविधाओं की घोषणा की भी सराहना की।

- **आईआईए ने लखनऊ स्थित कार्यालय में बजट पर चर्चा सत्र कार्यक्रम का किया आयोजन**
- **उद्यमी बोले- बजट से छोटे व्यवसायों के लिए ग्रोथ फंड और बड़े निवेश के मिलेंगे अवसर**

बजट पर चर्चा करते आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल व अन्य। ● अमृत विचार

पूर्व अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने चिंता जताई कि बजट एमएसएमई सेक्टर के लिए जरूरी स्तर का समर्थन नहीं देता है, यह बताते हुए कहा कि कई घोषणाएं लंबी अवधि की हैं। उन्होंने कहा कि बजट में एमएसएमई की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक तत्काल, एक साल के उपायों को शामिल किया जाना चाहिए था। वहीं, बैंकिंग समिति के चेयरमैन केके अग्रवाल ने सरकारी ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को टीआरईडीएस से जोड़ने के कदम का स्वागत किया, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए भुगतान चक्र तेज और लिक्विडिटी संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। कुल मिलाकर उद्यमियों ने बजट को नॉन-पॉपुलिस्ट लेकिन विकासोन्मुखी बताते हुए उद्योग जगत ने इसे सकारात्मक और दीर्घकालिक दृष्टि वाला कदम माना।

त्वरित टिप्पणी | चार स्तंभों – बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर टिका है वित्त मंत्री सीतारमण का 9वां बजट

बजट में तात्कालिक लाभ की बजाय भविष्य की नींव रखने पर जोर

वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को संसद में अपना 9वां बजट पेश करते हुए ''एक्शन ओवर एम्बिवैलेंस'' (दुविधा के ऊपर क्रियाशीलता) का मंत्र अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का ध्यान तात्कालिक चुनावी लाभ के बजाय भविष्य की नींव रखने पर है। यह बजट केवल आवंटन का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक बदलाव की रूपरेखा है, जो मुख्य रूप से चार स्तंभों-बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर टिका है। सरकार ने उपभोग - आधारित विकास (Consumption-led growth) के बजाय उत्पादकता-आधारित विकास (Productivity-led growth) का मार्ग चुना है। जहां 2025 का बजट व्यक्तिगत राहत और उपभोग बढ़ाने पर केंद्रित था, वहीं 2026 का यह बजट स्थिरता, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक दक्षता को प्राथमिकता देता है।

बुनियादी ढांचा और शहरी सुगमता : 12.2 लाख करोड़ का निवेश : इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन केवल सड़कों और पुलों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक लागत को कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रंखला में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। बेहतर कनेक्टिविटी का एक बड़ा सामाजिक प्रभाव यह होगा कि शहरों के बीच यात्रा का समय घटेगा, जिससे ''रिवर्स माइग्रेशन'' या संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब छोटे शहरों के लोग बड़े महानगरों में काम करते हुए भी अपने मूल निवास पर रह सकेंगे, जिससे बड़े शहरों में आवास की समस्या और मलिन बस्तियों का दबाव कम होगा। 2025 और 2026 के बजटों के बीच का अंतर वास्तव में भारत की आर्थिक परिपक्वता को दर्शाता है। यदि 2025 का बजट ''पैसा हाथ में देने वाला'' (Money in hand) बजट था, तो 2026 का बजट ''अवसर हाथ में देने वाला'' (Opportunity in hand) बजट है। पिछले वर्ष जहां टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाकर व्यक्तिगत राहत दी गई थी, वहीं इस वर्ष अनुपालन (Compliance) को सरल बनाने और विदेश यात्रा व शिक्षा पर TCS घटाने जैसे कदमों से मध्यम वर्ग के लिए वैश्विक अवसरों को सुगम बनाया गया है।

-प्रो. शिखा वर्मा, अर्थशास्त्र विभाग, बरेली कॉलेज

शिक्षा और कौशल : 'जॉब-रेडी' वर्क फोर्स का निर्माण

शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने ''किताबी ज्ञान'' से परे जाकर ''जॉब-रेडी'' कौशल पर ध्यान केंद्रित किया है। 15,000 स्कूलों में AVGC (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना और पांच नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप की घोषणा भारत को भविष्य की ''क्रिएटर इकोनॉमी'' के लिए तैयार करने का प्रयास है। सबसे महत्वपूर्ण पहल हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी छात्राओं के लिए STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) के द्वार खोलेगा। यह कदम न केवल महिला साक्षरता दर को सुधारेगा, बल्कि भारत के ''लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट'' (LFPR) में महिलाओं की हिस्सेदारी को भी गुणात्मक रूप से बढ़ाएगा।

स्वास्थ्य और केयर इकोनॉमी

एक सामाजिक बदलाव : स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट का दृष्टिकोण ''ईंट-पत्थर'' के निर्माण से आगे बढ़कर ''केयर इकोनॉमी'' की पूरी श्रृंखला को मजबूत करने वाला है। डेढ़ लाख मल्टी-स्किल्ड केयर गिवर्स का प्रशिक्षण और पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब का निर्माण स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम है। कैंसर की 17 दवाओं पर ड्यूटी खत्म करना मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करेगा। साथ ही, NIMHANS 2.0 के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को मुख्यधारा की चिकित्सा में शामिल करना एक ऐतिहासिक सामाजिक बदलाव है, जो भारत की उत्पादकता को मानसिक स्तर पर भी सुदृढ़ करेगा। यह दर्शाता है कि सरकार स्वास्थ्य को केवल बीमारी के इलाज के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण कल्याण (Well-being) के रूप में देख रही है।

शहर में आज

- सेंट्रल यूपी चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से बजट पर परिचर्चा होटल मेनोर जंक्शन रोड में शाम 8 :30 बजे।
- भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष व केंद्रीय बजट पर परिचर्चा डीडीपुरम चौराहे के पास रेस्टोरेंट में दोपहर 1 :20 बजे।
- रोहिलखंड मेनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से बजट पर परिचर्चा होटल ओबराय आनंद में शाम 5 :30 बजे।
- मॉडल टाउन स्थित श्री हरि मंदिर में श्री राम कथा शाम 4 से 7 बजे।
- अध्यात्म की गूंज परिवार की ओर से फागोत्सव सुरमयी कृष्णलीला आनंद आश्रम मंदिर में शाम 4 से 6 बजे तक।

शारदा उत्सव

एसआरएमएस रिद्धिमा में रविवार शाम श्री शारदा उत्सव का आयोजन हुआ। भरतनाट्यम के गुरुजनों और विद्यार्थियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उत्सव का आरंभ भरतनाट्यम के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, गणेश स्तुति, त्रिपुराष्टकम, अष्टलक्ष्मी, सरस्वती स्तुति से किया। भरतनाट्यम गुरु रोबिन ए ने गंगावतरण पर एकल और भरतनाट्यम गुरु तनया भट्टाचार्य के साथ शारदा नमोस्तुभ्यम को नृत्य प्रतिभा से दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। संचालन डॉ .आशीष कुमार ने किया। एसआरएमएस ट्रस्ट के संस्थापक देव मूर्ति, आशा मूर्ति, आदित्य मूर्ति, ऋचा मूर्ति, सुभाष मेहरा, डॉ. प्रभाकर गुप्ता, डॉ. अनुज कुमार, डॉ. शैलेश सक्सेना, डॉ. रीता शर्मा आदि मौजूद रहे। ● अमृत विचार

ज्ञान, भक्ति व धैर्य मानव जीवन को बनाते हैं सार्थक

● श्री हरि मंदिर में चल रही श्रीराम कथा में बोले डॉ. उमाकांतानंद

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार : श्री हरि मंदिर में चल रही श्रीराम कथा में रविवार को स्वामी डॉ. उमाकांतानंद सरस्वती महाराज ने जीवन में ज्ञान, भक्ति और धैर्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यही तत्व मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं।

महाराज ने नारद मुनि के चरित्र का वर्णन करते हुए उनकी भगवान के प्रति अटूट भक्ति, तप और वैराग्य को रेखांकित किया। कहा कि नारद मुनि का जीवन हमें निष्काम भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मनु महाराज के वृद्धावस्था में वनगमन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह साक्षात ज्ञान और भक्ति का मूर्त रूप है, जो मनुष्य को जीवन के अंतिम पड़ाव में ईश्वर की शरण में जाने का संदेश देता है। पांचवें दिन की कथा में भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के संहार की कथा ने श्रोताओं को भावविभोर किया। यह प्रसंग बुराई पर अच्छाई की विजय और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। उमाकांतानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि ऐसी कथाएं मानव को आत्मज्ञान, संयम और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। यह श्रीराम कथा डिवाइन श्रीराम इंटरनेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। डॉ. उमाकांतानंद फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में गुरु दीक्षा प्राप्त कर 16 वर्ष में गृह त्याग कर कठिन तपस्या की। प्रदीप सिंह चौहान, पीपी सिंह, संजय अग्रवाल, रविशरण सिंह चौहान, मालती देवी आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

प्रेसवार्ता में मौजूद स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती व अन्य। ● अमृत विचार

विषम परिस्थिति में मन को संतुलित करने की सीख रामायण से मिलती

बरेली : हरि मंदिर परिसर में दोपहर में स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती ने प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि विषम परिस्थिति में मन को संतुलित करने की सीख रामायण से मिलती है। भगवान श्रीराम जब इस धरती पर आते हैं तो चमत्कार नहीं करते, वह जीकर दिखाते हैं। माता-पिता की आज्ञा का कैसे पालन किया। श्रीराम कथा लोगों को उनके आदर्शों पर चलने की सीख देती है, ताकि मर्यादा जीवन में आ सके। परिवार और जीवन में सौहार्द बढ़े।

कोई भी नाम मतदाता सूची में शामिल होने से न रह जाए

कैंप कार्यालय पर ईआरओ के साथ समीक्षा बैठक करते डीएम। ● अमृत विचार

● डीएम ने ईआरओ के साथ फॉर्म 6, 7 व 8 प्रगति की समीक्षा की

बरेली, अमृत विचार: जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने रविवार को कैंप कार्यालय पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के संबंध में सभी ईआरओ के साथ समीक्षा बैठक कर फॉर्म 6, 7 व 8 की प्रगति की समीक्षा की।

डीएम ने 31 जनवरी को प्राप्त दावे एवं आपत्तियों से संबंधित सूचना मांगने के बाद सभी ईआरओ से समीक्षा कर प्रगति जानी। ईआरओ को निर्देशित किया है कि फॉर्म 6 को प्राप्त करें, जिससे कोई मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से न रह जाए। निर्देश दिए कि नो मैपिंग के संबंधित नोटिस की सुनवाई भी प्रभावी ढंग से करें। एईआरओ की भी समीक्षा समस्त ईआरओ करें।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इशिता किशोर, एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, रामजनम यादव आदि उपस्थित रहे।

राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना हमारा दायित्व

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बसंत विहार मठ लक्ष्मीपुर बस्ती में आयोजित किया हिंदू सम्मेलन, बड़ी संख्या में जुटे लोग

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रविवार को गुरु गोविंद सिंह नगर की बसंत विहार-मठ लक्ष्मीपुर बस्ती में आयोजित हिंदू सम्मेलन में महानगर कार्यवाह प्रोफेसर विमल ने कहा कि संघ शाखाओं के माध्यम से स्वयंसेवक निर्माण का कार्य करता है। राष्ट्रभक्ति और हिंदू स्वाभिमान की भावना से भरे ये स्वयंसेवक दर्जनों संगठनों के माध्यम से राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। भारत हमारा राष्ट्र है, इसको हर तरह से समृद्ध, श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना हमारा दायित्व है, इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा।

हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रदेश महामंत्री डॉ सुरेंद्र सिंह बगौर ने कहा कि हिंदू धर्मावलंबियों को अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन एक खास मजहब के लोग हमारी बहन बेटियों को फंसाने के लिए हाथ में कलावा बांधकर अपना नाम बदलकर घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपने ढाबे और रेस्टोरेंट भी हिंदू नाम से खोल रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। बेटियों और बहनों को जिहादी मानसिकता के लोग घर से उठाकर ले जा रहे हैं। बहनों को आत्मरक्षा के गुर सीखने होंगे, सरकार भी महिलाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर जोर दे रही है। अगस्त्य के मुनी आश्रम के महंत पंडित केके शंखधार ने कहा कि दुनिया में सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। कहा कि जो लोग धर्म को धारित करते हैं, वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने कहा कि हमें अपने घर का वातावरण इस तरह का बनाना होगा ताकि बेटियां अपनी संस्कृति और परंपराओं से परिचित हो सकें। संचालन करते हुए नाथ नगरी सुरक्षा समूह के महानगर अध्यक्ष दुर्गेश गुप्ता ने कहा कि आपसी भेदभाव भूल कर परस्पर प्रेम का वातावरण तैयार करना होगा। कार्यक्रम अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। सह महानगर कार्यवाहक प्रसून, महानगर शारीरिक प्रमुख विशेष, महानगर प्रचार प्रमुख विकास सक्सेना, विभाग घुमंतू कार्य प्रमुख महेश, मुरारी लाल गुप्ता, प्रशांत, प्रेम शंकर, वेद प्रकाश, अपुल श्रीवास्तव, सुधांशु सक्सेना, रविंद्र, और पार्षद शशि सक्सेना आदि उपस्थित रहे। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ● अमृत विचार

बसंत विहार-मठ लक्ष्मीपुर बस्ती में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मंचासीन अतिथि।

पंच परिवर्तन से रामराज्य की कल्पना को कर सकते हैं साकार : सुरेश चंद्र

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार: संत रविदास जयंती पर रविवार को संत रविदास हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति की ओर से वीरसावरकर नगर बस्ती में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता सुरेश चंद्र ने कहा कि शताब्दी वर्ष में संघ ने समाज से पंच परिवर्तन का आह्वान किया है, जिनमें कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य एवं स्व का बोध है। इनका पालन कर हम रामराज्य की कल्पना को साकार कर सकते हैं।

केदारपुरी महाराज ने कहा कि हमें अपने बच्चों को संस्कृति एवं महापुरुषों के बारे में अवश्य बताना चाहिए, इससे बच्चों के मन में संस्कृति एवं महापुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होगा। मातृ शक्ति के रूप में बृज मोहिनी दासी ने कहा कि नारी जब पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है तो कदमों को गिनती दोगुनी हो जाती है, इसीलिए प्रत्येक परिवार में पति पत्नी के मध्य आपसी सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व मालवीय नगर प्रखंड की विश्व हिंदू परिषद की टीम ने अतुल शर्मा के नेतृत्व में भजनों की प्रस्तुति दी। अध्यक्षता डॉ विवेक गुप्ता ने की। समिति अध्यक्ष एड. अजय अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया, अतिथि स्वागत मयंक गोयल व कपिल चंदानी ने किया। संचालन संजय शुक्ला ने किया। डॉ विवेक गुप्ता ने निशुल्क डायबिटीज चेकअप कैंप लगाया। सम्मेलन में हनुवन सिटी, अंबिका बिहार, बन्नूवाल नगर, पीएनबी कॉलोनी, सिद्धार्थ कुंज आदि शामिल हुए। विभाग प्रचारक कृष्ण कुमार, मयंक साधु , देवेंद्र सिंह सोम, सचिन सक्सेना, अवधेश सक्सेना, दुजेंद्र गुप्ता, सौरभ तिवारी, शुभ राठौर, योगेंद्र गंगवार, अमित गोयल, विजय शंकर मिश्रा, वरुण अग्रवाल, पंकज महंत, डॉ राजेश गंगवार, डॉ राजीव सिंह, कमलेश वर्मा, पीयूष अरोरा, आलोक दीक्षित, यतेंद्र गंगवार, संजय पाठक आदि उपस्थित रहे।

वीरसावरकर नगर बस्ती में हिंदू सम्मेलन में मंचासीन अतिथि। ● अमृत विचार

● हिंदू सम्मेलन में पंच परिवर्तन करने का किया आह्वान

● वीरसावरकर नगर बस्ती में आयोजित हुआ सम्मेलन

सिटी डायरी

अमन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री से की भेंट

बरेली, अमृत विचार : भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अमन सक्सेना ने रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। अमन ने महानगर से जुड़े कई विकास कार्यों, युवाओं की समस्याओं एवं संगठनात्मक विषयों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष चर्चा कर खेल सुविधाओं के विस्तार पर पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को सुन कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने युवा मोर्चा की ओर से किए जा रहे संगठनात्मक कार्यों की सराहना की। अमन ने मुख्यमंत्री को कामधेनु गाय की मूर्ति भी भेंट की।

मदर्स पब्लिक स्कूल में मनाया विदाई समारोह

बरेली, अमृत विचार : मदर्स पब्लिक स्कूल की बरेली शाखा में रविवार को कक्षा 12 के छात्रों का विदाई समारोह मनाया गया। जिसमें कक्षा 11 के छात्रों ने कक्षा 12 के छात्रों को विदाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक राजेश यादव और प्रधानाचार्य आईपीएस चौहान ने किया। कक्षा 11 के छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रबंधक ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए अनुशासन और आत्मविश्वास का होना अनिवार्य है। प्रधानाचार्य ने बच्चों से कहा कि आपको हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ज्योति सक्सेना, गोविन्द, गुलबसर, निधि जौहरी, ललित जोशी, प्रदीप, अभिषेक, शाजी आलम, मकीम, आरएस शर्मा, फारुक, विवेक आदि मौजूद रहे।

देवाशीष मिस्टर फेयरवेल, निष्ठा मिस फेयरवेल चुनी गईं

बरेली, अमृत विचार : बेदी इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को कक्षा 12 के विद्यार्थियों के सम्मान में "हास्ता- ला- विस्ता" विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चेयरमैन अमनदीप बेदी व प्रधानाचार्य जेके साहनी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। विदाई समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गये। कार्यक्रम में देवाशीष चतुर्वेदी मिस्टर फेयरवेल और निष्ठा सक्सेना को मिस फेयरवेल चुना गया। इस भावुक क्षणों के बीच साथियों के साथ बीते पलों के याद कर विद्यार्थियों की आंखें नम हो गई।कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न भेंट किये गये।

अधिकारी और कर्मचारियों को किया सम्मानित

बरेली, अमृत विचार : श्री वेदांता अस्पताल व श्री नाथ मेडीसिटी अस्पताल में महानिदेशक स्वास्थ्य ने अस्पताल के कुशल अधिकारी और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस के अवसर सम्मानित किया। इसमें अखिलेश पराशर, विजय, महीपाल, नावेद, प्रामोद, आशीष राना, वैभव गौड़, राजकुमार, शगुन गंगवार, अफरोज, वर्षा गौड़ आदि शामिल रहे।

92 वें जश्न ए बुखारी शरीफ को लेकर हुई बैठक

बरेली, अमृत विचार : मदरसा दारुल उलूम मजहरे इस्लाम मस्जिद बीबीजी बिहारीपुर में रविवार को मुफ्ती ए आजम ट्रस्ट के अध्यक्ष मुफ्ती अनस रजा खां कादरी की सरपरस्ती में बैठक हुई। प्रवक्ता हाफिज जुबैर रजा खालिदी ने बताया कि सोमवार को सुबह 9 बजे मदरसा दारुल उलूम मजहरे इस्लाम में 92 वें जश्न ए बुखारी शरीफ का आयोजन होगा। जिसमें 20 मुफ्ती, 20 फजीलत, 15 कारी, 6 हाफिज को दस्तारबंदी कर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मंगलवार को बाद नमाजे इशा जलसा की महफिल होगी। कार्यक्रम की सरपरस्ती मुफ्ती अनस रजा खां कादरी करेंगे। सैय्यद शोएब रजा कादरी, मुफ्ती सगीर अहमद बरकाती, मुफ्ती तौसीफ रजा नूरानी, जाकिर हुसैन नूरी आदि मौजूद रहे।

गुरु हरि राय व संत रविदास का प्रकाश पर्व मनाया

कीर्तन करता रागी जत्था। ● अमृत विचार

बरेली, अमृत विचार : गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सुभाषनगर में कमेटी के सहयोग से गुरु हरि राय व भगत रविदास का प्रकाश पर्व बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। कीर्तनी जत्थे ने साची प्रीति हम तुम सिउ जोरी, तुम सिउ जोरि, अवर संगि तोरी, का कीर्तन गायन करके संगत को निहाल किया। भगत रविदास की वाणी का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ने को मिलता है, समाप्ति के बाद गुरु का अटूट लंगर बांटा गया। कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह नागपाल, महासचिव परदमन सिंह, सुरिंदरजीत सिंह छाबरा, अमरीक सिंह, गुरविंदर सिंह, मिंटू चावला, हरप्रीत सिंह गोलू, हरभजन सिंह मोंगा, साहिब सिंह, रवि अरोरा, मिक्की जोहर, भूपिंदर सिंह, इंदरपाल गोल्डी रहे।

● कीर्तनी जत्थे ने कीर्तन गायन से संगत को निहाल किया

अमृत विचार

www.amritvichar.com

बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम

बरेली, अमृत विचार : सीए प्रदीप का कहना है कि बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम है। उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही छोटे व्यापारियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर अगस्त करना स्वागतयोग्य निर्णय है। बजट में दी गई छोटी-छोटी सहूलियतें कारोबार को आसान बनाएंगी। कुल मिलाकर यह एक सकारात्मक बजट है। इससे उद्यमियों को राहत मिलेगी।

बजट नए भारत की कल्पना को साकार करने वाला : दुर्विजय

भाजपा महानगर के सभी मंडलों में एलईडी स्क्रीन लगाकर बजट लाइव देखा गया, बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की रही मौजूदगी

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार : भाजपा महानगर के सभी मंडलों में एलईडी स्क्रीन लगाकर बजट लाइव देखा गया। डीडी पुरम मंडल में हुए कार्यक्रम में भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना और मेयर डॉ उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल आदि ने बजट देखा।

क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य का कहना है कि बजट नए भारत की कल्पना को साकार करने वाला है, सभी धर्मों, जाति के लोगों को ध्यान में रखकर बजट लाया गया है। हर वर्ग को लाभ पहुंचे, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने की जो घोषणा की है, वह नए भारत की कल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है।

क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत के संकल्प को साकार करने का माध्यम है। प्रदेश उपाध्यक्ष/ब्रज क्षेत्र के प्रभारी संतोष सिंह, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता, महामंत्री प्रभु दयाल लोधी, प्रत्तेश पांडे, डॉ तृप्ति गुप्ता, विष्णु शर्मा, बंटी ठाकुर, मनीष अग्रवाल, विशाल मल्होत्रा, पवन अरोड़ा, रामकृष्ण शुक्ला, विपिन भास्कर, मनमोहन सवरवाल, शिशिर शर्मा, योगेश कुमार बंटी, दीपक गुप्ता, ईशान सक्सेना, संजीव द्विवेदी, नरेंद्र सिंह, अतुल कपूर, पुष्पेंद्र शुक्ला, अजय चौहान, शशि सक्सेना, अरुण सिंह मौजूद रहे।

डीडीपुरम में बजट के लाइव प्रसारण को देखते भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि। ● अमृत विचार

आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मजबूत करेगा : डॉ. एमपी आर्य

बरेली, अमृत विचार : भाजपा जिला बरेली की ओर से एलईडी स्क्रीन पर केंद्रीय बजट लाइव देखने के लिए सौ फुटा रोड स्थित एक बैंक्वेट हाल में कार्यक्रम किया गया। पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि, मोर्चों के अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बजट भाषण को सुना और देश की आर्थिक दिशा से जुड़े बिंदुओं को समझा। नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्य ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग का ध्यान रखा है। यह बजट देश के समग्र विकास को गति देगा और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मजबूत करेगा। बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और आर्थिक अनुशासन का संतुलित उदाहरण है। जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा ने कहा कि यह बजट विकासोन्मुखी है और इसे हर वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, पवन शर्मा, हरिशंकर गंगवार, वीरपाल गंगवार, डॉ. निर्भय गुर्जर, मेघनाथ सिंह कठेरिया, चंचल गंगवार, अजय सक्सेना, अंकित माहेश्वरी, अभय चौहान, राहुल साहू, शिवमंगल राठौर, भूपेंद्र कुर्मी, योगेश पटेल, वीरपाल मौर्य, अमित गुप्ता, किरण पटेल, पूजा गंगवार, धर्म विजय गंगवार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इनकम टैक्स में सरलीकरण अच्छा, कुछ प्रावधानों से परेशानी

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार : रामपुर रोड स्थित होटल में रविवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोसाइटी के तत्वाधान में बजट पर परिचर्चा आयोजित की गयी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सीए रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने इनकम टैक्स में हुए कुछ सरलीकरण को अच्छा बताया, लेकिन कुछ परिवर्तन उद्यमियों को परेशानी बढ़ाने वाला बताया।

अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि बजट में कहीं न कहीं सरकार की विकास कर देश को आगे बढ़ाने की स्पष्ट मंशा झलकती है। इनकम टैक्स में कुछ छूटों का प्रावधान समाप्त करने व पेनाल्टी या कानूनी कार्रवाई की जगह पेनाल्टी व वैधानिक कार्रवाई, 2 वर्ष की जेल का प्रावधान किया जाना उद्यमियों व व्यापारियों के लिए भारी निराशाजनक प्रावधान किया है। इससे लोग हतोत्साहित होकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाने से पहले विचार को बाध्य होंगे। रात-दिन कड़ी मेहनत कर अपने कर्मचारियों के परिवार, अपने परिवार, सामाजिक सरोकारों के माध्यम से जनता के हितों के

रामपुर रोड के एक होटल में हुए कार्यक्रम में बजट लाइव देखते उद्यमी और सीए। ● अमृत विचार

- **इनकम टैक्स में कुछ छूटों को समाप्त करने व वैधानिक कार्रवाई चिंता बढ़ाने वाले प्रावधान**
- **बजट में कहीं न कहीं सरकार की विकास कर देश को आगे बढ़ाने की स्पष्ट मंशा झलक रही**
- **चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोसाइटी के तत्वाधान में बजट पर आयोजित की गयी परिचर्चा**

अलावा सरकार को टैक्स देकर देश के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाले को पेनाल्टी व जेल दोनों की तरफ ले जाना चिंता का विषय है। ये विकास विरोधी निर्णय है। सरकार इसी टैक्स से तमाम विकास का खाका खींचने को दम भरती है। ऐसे में टैक्स देने वाला व्यापार बढ़ाने से बचेगा जो आज नहीं तो कल सरकार की चिंता का कारण बनेगा।

जीएसटी पर प्रमुख वक्ता के रूप में सीए कपिल वैश्य ने बजट को विकास पूरक तो बताया लेकिन सरलीकरण पर और आवश्यकता बतायी। अन्य वक्ताओं ने भी बजट के विभिन्न अच्छे बुरे पहलुओं पर अपने विचार रख सुझाव प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में सीए प्रकाश चंद्र षर्मा, सीए मनोज मंगल, सीए शरद मिश्रा, सीए पवन अग्रवाल ने भी अपने रखे। सचिव डॉ. प्रमेंद्र माहेश्वरी ने मेडिकल क्षेत्र के लिए की गयी घोषणाओं को जन हितैशी बताया। मुख्य रूप से डॉ मनीष शर्मा, डॉ विनय खंडेलवाल, डॉ विमल भारद्वाज, डॉ नीरज सक्सेना, पीयूष अग्रवाल, रवि अग्रवाल, उमेश निमानी, आशुतोष शर्मा, डॉ एमएस बासु, इं सुधीर गुप्ता, जयप्रकाश देवनानी, सिद्धार्थ जसोरिया, वरुण गुप्ता, दीपक मलिक, पवन गुप्ता, दिनेश सिंह, हेमंत अग्रवाल, सुनीत मोना, लकी मोगा, पुष्पेंद्र कुमार, सुभाष मेहरा आदि उपस्थित रहे।

सरकारी कर्मियों पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ

कार्यालय संवाददाता, बरेली

- **सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की बजट पर रही मिली-जुली प्रतिक्रिया**

अमृत विचार : आम बजट को लेकर सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ का कहना है कि कर प्रणाली में कोई बदलाव न होने से सरकारी कर्मचारियों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, वहीं इस बार बजट में सेवानिवृत कर्मचारियों और पेंशनरों की पूरी उपेक्षा करने की बात कही जा रही है। बीमा क्षेत्र में भी कोई बदलाव न होने से लाखों लोग टकटकी लगाए देखते रह गए।

बजट का मुख्य फोकस कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर रहा है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेक इन इंडिया को रफ्तार मिलेगी और भारत तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। देश में 9 नए रेल कॉरीडोर स्थापित करने और 20 नए जलमार्ग विकसित करने से बड़ी संख्या में कुशल एवं अकुशल युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। **सुरेश बाबू मिश्रा**, साहित्य भूषण एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य

महंगाई भत्ता, सेवाओं से जुड़े कुछ प्रावधान राहत देने वाले हैं, लेकिन सीधी कर राहत सीमित होने के कारण सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई राहत नहीं है। महंगाई के दौर में टैक्स स्लैब न बढ़ने से वास्तविक आय पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और पूंजी समर्थन पर जोर से बैंकों की स्थिरता और कार्यक्षमता को बल मिलेगा। बजट संतुलित है, लेकिन कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के लिए कर के प्रावधानों पर और ठोस राहत की जरूरत महसूस होती है। – **नवींद्र कुमार**, उप महामंत्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन

बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं मिला। कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए भी कोई घोषणा नहीं की गई। आठवें वेतन आयोग के संबंध में भी बजट की कोई व्यवस्था नहीं की गई, रेलवे में खाली पड़े लाखों पदों को भरे जाने के संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। रेलवे में कर्मचारियों के आवासों की भारी कमी है। इनकम टैक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार का बजट कर्मचारियों के हित में नहीं रहा। – **बसंत चतुर्वेदी**, महामंत्री एनई रेलवे मजदूर यूनियन

तीन सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विलय की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा में राहत के लिए भी कोई घोषणा नहीं हुई। लाखों लोग इस ओर टकटकी लगाए देखते रहे गए। जीएसटी शून्य करके सरकार पहले भले ही राहत दे चुकी है, लेकिन बजट में कोई राहत न दिए जाने का असर बीमा क्षेत्र की कई कंपनी के शेयर्स में गिरावट के रूप में देखा जा सकता है। – **अनुज अग्रवाल**, बीमा विशेषज्ञ

बजट सभी को साथ लेकर चलने वाला : धर्मपाल

आंवला अमृत विचार : कैंप कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने केंद्र सरकार के बजट को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ देखा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट सभी को साथ लेकर चलने वाला बजट है । यह आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाया गया है । इस दौरान अनमोल गुप्ता , हरीश चौहान ,सुनील श्रीवास्तव, रामनिवास मौर्या, इंद्रपाल सिंह, रामदीन सागर, आशू सिंह आदि लोग उपस्थित रहे ।

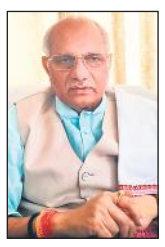

बजट से उम्मीदें हुई धराशायी

देश के लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सब धराशायी हो गईं। आम आदमी, व्यापारी, मध्यवर्गीय, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, बुजुर्गों, छात्र-छात्राओं सभी के हाथ निराशा लगी। लोगों को उम्मीद थी की आयुष्मान कार्ड की लिमिट 5 लाख से 10 लाख की जाएगी, इसमें भी निराशा हाथ लगी। – **मिर्जा अशफाक सकलैनी**, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

बजट आम आदमी की पहुंच से दूर का बजट है। भाजपा सरकार ने अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं ताकि वह और मजबूत हो सकें। देश का मजदूर, अन्नदाता, बेरोजगार नौजवान और व्यापारी आज सभी निराश है। – **डॉ. केबी त्रिपाठी**, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

कागजों में सजा बजट, भाषणों में विकास कर रहा है, पर किसान, मजदूर फिर खाली हाथ रहा। बजट का फोकस उच्च-मूल्य कृषि, मत्स्य पालन, एआई टूल जैसे क्षेत्रों में ऋण विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा, लेकिन ये घोषणाएं जमीनी स्तर पर लागत से कम दाम पर बिकती फसल और कर्ज जाल का समाधान नहीं करतीं। बजट निराश करने वाला है। – **पंडित राज शर्मा**, प्रवक्ता कांग्रेस

भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को एन ई रेलवे मेन्स कांग्रेस, कारखाना मंडल इज्जतनगर सिरे से खारिज करती है। यह बजट स्पष्ट रूप से पूंजीपति, कॉर्पोरेट घरानों, निजी उद्योगों एवं ठेकेदार वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है, जबकि रेल कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों एवं श्रमिक वर्ग की घोर उपेक्षा की गई है। – **रजनीश तिवारी**, मंडल मंत्री, एन ई रेलवे मेन्स कांग्रेस इज्जतनगर

राहत | **डायबिटीज और कैंसर की दवाओं की कीमतें कम करने पर बजट को बताया अच्छा**

सस्ती दवाओं से मरीजों की जेब का बोझ घटा

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार : आम बजट से जिले में दवा विक्रेताओं में खुशी का माहौल है। विशेष रूप से डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने का निर्णय लिया गया है, जिससे मरीज अब आसानी से इन जरूरी दवाओं को खरीद पाएंगे।

दवा विक्रेताओं का कहना है कि ये दवाएं काफी महंगी होने के कारण कई मरीजों की जेब पर भारी पड़ती थीं, सरकार की इस पहल से आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी।

सरकार के इस फैसले का सभी दवा व्यापारी स्वागत करते दिखे और कहा कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह अच्छा बजट बनाया गया। दवाओं की कीमतों में कमी से मरीजों की पहुंच आसान होगी और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में भी कमी आएगी। बजट में इस निर्णय को स्वागत योग्य कदम माना है। गंभीर बीमारियों के दवाएं सस्ती होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार ने स्वास्थ्य के मोर्चे पर बहुत अच्छा फैसला लिया है। बजट में दवाओं की कीमतें घटाने से मरीजों की परेशानी कम होगी। डायबिटीज और कैंसर जैसी दवाओं का सस्ता होना सीधे आम आदमी के जीवन पर असर डालेगा। हम विक्रेता भी खुश हैं क्योंकि अब ग्राहक आसानी से दवा खरीद पाएंगे और दवा की पहुंच सभी तक होगी। – **दुर्गेश खटवानी**, अध्यक्ष, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन

दवाएं महंगी होने से कई लोग उन्हें नहीं खरीदते थे, डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो आम होती जा रही है। इसकी दवा भी सस्ती कर दी गई है। जल्द, नई एमआरपी की दवा आ जाएगी। उसी हिसाब से फिर दवाओं को बेचा जायेगा। सरकार का यह फैसला बहुत सराहनीय है। इस बजट से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। यह बहुत अच्छी बात है। -**जितेंद्र**, दवा विक्रेता

बजट में दवाओं की कीमतें कम करने का निर्णय बहुत राहत देने वाला है। डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं पहले काफी महंगी थीं और कई मरीज इन्हें खरीदने में परेशान रहते थे। अब सस्ती दवाओं से मरीजों को लाभ मिलेगा। आम आदमी भी आसानी से इलाज करा सकेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बजट काफी सकारात्मक कदम है।-**अविनेश मित्तल**- पूर्व जिलाध्यक्ष, रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन

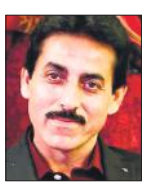

बजट आम आदमी के लिए राहत से भरा हुआ है। दवाओं के सस्ते होने से अब ग्राहक और ज्यादा देखने को मिलेंगे. पहले कई लोग महंगी होने की वजह से दवा नहीं खरीदते थे या जेनरिक लेने पर मजबूर होते थे। कई बार दवा चेंज होने से वह असर नहीं करती थी, लेकिन अब मरीज आसानी से जरूरी दवा खरीदेगा, जिससे बाजार में हलचल तेज रहेगी।- **मुकेश कुमार**, दवा विक्रेता

रोहेलखण्ड कैंसर इंस्टीट्यूट, बरेली
कैंसर की संपूर्ण देखभाल एक ही छत के नीचे
A unit of Rohilkhand Medical College Hospital

200 Bed का Cancer अस्पताल
अब आपके शहर के बीच में

World Cancer DAY
के उपलक्ष में 4 फरवरी को मुफ्त परामर्श
स्तन कैंसर की जाँच (Mammography) मात्र 200/- में
बच्चेदानी के कैंसर की जाँच मात्र 100/- में

रेडियोथैरिपी के लिए ट्रुबीम एसटीएक्स (लीनियर एक्सलरेटर)
High Definition MLC,SRS,SBRT,IMRT, IGRT,Rapid ARC, RGSC, VMAT, 3D CRT, 6D Couch, 3 Energy Phototherapy, 5 Energy Electron Therapy
बरेली का एकमात्र PET CT कैंसर की स्टेज जानने लिए

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत PM-JAY
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अन्तर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

हमारी सेवाएं
•सर्जिकल ऑन्कोलॉजी • रेडिएशन ऑन्कोलॉजी • डे-केयर कीमो थैरेपी • इम्यूनोथेरेपी • कैंसर आई.सी.यू • फ्रोजन सेक्शन और इम्यूनोहिस्टेकैमिस्ट्री • मैमोग्राफी • कैंसर के रोकथाम की ओपीडी • टर्मिनल कैंसर मरीजो की देखभाल • इण्टरवेंशनल रेडियोलॉजी

रोहेलखण्ड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कैम्पस, नज़दीक सुरेश शर्मा नगर, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली उ.प्र.-243006
हैल्पलाइनः 7891235003, पैट सीटी बुकिंग के लिए +91 9811187117, आपातकालीन-9258116087
www.rohilkhandcancerinstitute.com
follow us on /rohilkhand cancer intitute

अमृत विचार

बरेली, सोमवार, 2 फरवरी 2026

बजट प्रतिक्रिया

पिछले बजट की तुलना में इस बजट में सरकार ने युवाओं को नौकरियों के अधिक अवसर देने करने का वादा किया है। यह अच्छी बात है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में नौकरियों के लिए बजट बढ़ाया गया है। **-डॉ. महेंद्र कुमार सक्सेना,** सेवानिवृत्त प्रवक्ता

कर्मचारियों एवं कामगारों के लिए बजट में कोई राहत नहीं मिली। कोरोना काल में काटे गए भत्तों, पुरानी पेंशन बहाली एवं ठेका प्रथा समाप्त करने को लेकर कोई बात बजट में नहीं की गई जिससे कर्मचारी वर्ग निराश है। **-डॉ. अंचल अहेरी,** चेयरमैन, संघर्ष समिति राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

बजट सतत विकास पर केंद्रित है, जहां एक तरफ राजकोषीय घाटे को कम करने की चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता की बढ़ती उम्मीदें। इनकम टैक्स छूट बढ़ती तो सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता था। **-अभिनन्दन गुप्ता,** सीए

बजट में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कोई घोषणा न करके सरकार ने एक बार फिर से अधिसंख्य कर्मचारियों और नौकरी पेशा वर्ग को निराश किया है। इससे स्पष्ट है कि इस वर्ग की समस्याएं और हित सरकार के विमर्श में है ही नहीं। **- जयेंद्र शेखर गुप्ता,** मंडल संयोजक, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, कारखाना मंडल इज्जतनगर।

विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करता हुआ रोड मैप तैयार किया है, साथ ही इक्कीसवीं शताब्दी को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया है, जिसमें पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप के साथ शहरों को और विकसित करने का बजट का प्रावधान किया है। **- पंडित हरिओम गौतम,** सदस्य मंडल रेल परामर्शदात्री समिति

बजट व्यापारी और समाज के हित में है, 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए यह बजट भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट चीन और अमेरिका की भारत विरोधी मुहिम की भी हवा निकालेगा और अमेरिका के टैरिफ की भी काट बनेगा। **-जफर बेग,** संरक्षक, बरेली मर्चेंट एसोसिएशन

बरेली में एम्स स्थापना की बढ़ी उम्मीद, पैरवी होगी तेज

कार्यालय संवाददाता, बरेली

- **मुख्यमंत्री भी पूर्व में बरेली में एम्स की जरूरत बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेज चुके हैं पत्र**
- **बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना का किया गया प्रावधान**
- **बरेली में एम्स की मांग वर्षों पुरानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से कई बार हो चुकी मांग**

अमृत विचार: केंद्रीय बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना की बात शामिल करने के बाद बरेली शहर में ''एम्स'' की स्थापना की उम्मीद बढ़ गयी है। एम्स स्थापना की वर्षों पुरानी मांग को बल मिला है। जिले के जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कई बार एम्स की मांग कर चुके हैं। कुछ माह पूर्व जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजा जा चुका है।

बरेली टू टियर शहरों में शामिल होने के साथ दिल्ली-लखनऊ के मध्य में है। यहां एम्स की स्थापना की प्रबल संभावना भी है। बरेली में एम्स बनने से बरेली व मुरादाबाद मंडल के लोगों को भी लाभ मिलेगा। बरेली शहर में एम्स की स्थापना के लिए फतेहगंज पश्चिमी में बंद पड़ी रबर फैक्ट्री की सैकड़ों एकड़ भूमि भी उपलब्ध है। इसी भूमि पर एम्स की स्थापना की मांग वर्षों से की जा रही है। सांसद रहते हुए संतोष गंगवार, सांसद छत्रपाल गंगवार, मीरगंज विधायक डॉ. डीसी वर्मा, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, बिथरी विधायक डॉ राघवेंद्र शर्मा, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप आदि एम्स की स्थापना कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत मिलने के साथ पूर्व में पत्र लिख चुके हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना बरेली में कराने के लिए पूर्व के प्रयास और तेज होंगे। बरेली में एम्स बनने से कई जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। वैसे भी आगरा से दिल्ली डेढ़-दो घंटे व मेरठ से एक घंटे दूर है। जबकि बरेली से चार से पांच घंटे लगते हैं। एक दो दिन में लखनऊ जाने पर मुख्यमंत्री से फिर इस संबंध में बातचीत करेंगे।

– संजीव अग्रवाल, कैंट विधायक

बजट में एम्स के प्रावधान होने से बरेली में इसकी स्थापना कराने के हर संभव प्रयास होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की मांग सबसे ज्यादा बरेली से उठी है। जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर उच्च स्तर पर एम्स की स्थापना की बात उठाएंगे। बरेली में एम्स बनने से हजारों लोगों को लखनऊ और दिल्ली की दौड़ लगाने से राहत मिलेगी। **–दुर्विजय सिंह शाक्य,** अध्यक्ष बृज क्षेत्र भाजपा

ट्रामा सेंटर बनेगा पर बरेली में पहले से बना है

बरेली : बजट में हर जिले में ट्रामा सेंटर बनाए जाने का प्रावधान है। बजट के अनुसार बरेली में भी बनना चाहिए, लेकिन बरेली में पहले से ट्रामा सेंटर सफेदहाथी बना हुआ है। भवन बनकर खड़ा है, लेकिन स्टाफ की तैनाती नहीं हुई है, इस वजह से इसका संचालन नहीं हुआ है। नए ट्रामा सेंटर खोले जाने के क्रम में पहले से बने ट्रामा सेंटर में मैनपावर तैनात होने की उम्मीद बढ़ गयी है।

सत्ता को भाया..विपक्ष को रास नहीं आया बजट

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार: केंद्र सरकार का आम बजट सत्ता पक्ष को विकासोन्मुख और दूरदर्शी नजर आया, वहीं विपक्ष ने इसे आम जनता विरोधी बताते हुए तीखा हमला बोला।

सरकार और उसके समर्थकों का दावा है कि बजट में कर सुधार, निवेश प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और स्टार्टअप्स पर फोकस कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बजट में महंगाई, बेरोजगारी और मध्यम वर्ग की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है।

बजट आम जनता के साथ एक और धोखा है। बढ़ती महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी, किसानों की लगातार उपेक्षा और युवाओं के भविष्य पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। यह बजट न राहत देता है, न भरोसा जगाता है सिर्फ जुमलों और आंकड़ों का खेल बनकर रह गया है।

– शिवचरन कश्यप, पूर्व जिलाध्यक्ष, सपा

यह बजट आम जनता नहीं बल्कि केवल पांच प्रतिशत अमीर वर्ग के हित में बनाया गया है। सरकार गरीब, किसान और मिडिल क्लास से वोट लेकर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। महंगाई, रोजगार, शिक्षा और किसान समस्याओं पर बजट नहीं था। यह बजट केवल उद्योगपति मित्रों का बजट रहा।

–मुहम्मद साजिद, प्रदेश प्रवक्ता, सपा

बजट विकसित भारत की उड़ान को पंख देने वाला है। बजट में फार्मास्यूटिकल्स संस्थान, केमिकल पार्क और बालिकाओं के लिए हॉस्टल निर्माण जैसे कदम उठाए गए हैं। इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं।

–डा. उमेश गौतम, मेयर

बजट में योजनाओं और परियोजनाओं के नाम तो बड़े-बड़े हैं, लेकिन, जमीनी परिणाम छोटे नजर आते हैं। बजट में महंगाई पर लगाम लगाने या आयकर में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। आयकर में छूट का प्रावधान न किए जाने से आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। आठवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ेंगे, ऐसे में उन्हें ज्यादा टैक्स देना होगा। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार गारंटी जैसे बुनियादी मुद्दों पर मौन है।

– डा. जयपाल सिंह, जिलाध्यक्ष, बसपा

बजट विकसित भारत और प्रधानमंत्री के नए और ऊर्जावान भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प के लिए है। हर क्षेत्र का समुचित अध्ययन करने के बाद एक नया नक्शा तैयार किया गया है। यह एक समग्र बजट है जो न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि इसे विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगा।

–रश्मि पटेल, अध्यक्ष, जिला पंचायत

बजट में सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया, जो इतना बड़ा राज्य है। जहां किसान, मजदूर और गरीब लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि देश के गरीब, कमजोर और आम लोग निराश हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेयर बाजार धराशायी हो गया है और कमोडिटी बाजारों को भारी नुकसान हुआ है। **–नीरज मौर्य,** सांसद आंवला

बजट विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का संतुलित रूप से ध्यान रखा गया है। विकास, निवेश और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए यह बजट देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का भरोसा देता है।

–एड. अनुज, जिलाध्यक्ष अपना दल (एस)

बजट में बड़े-बड़े ऐलान आम आदमी, किसान, युवाओं और मध्यम वर्ग की मुख्य समस्याओं जैसे बेरोजगारी, महंगाई और असमानता पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह बजट कॉर्पोरेट परस्त और जन विरोधी है। बजट में महंगाई पर लगाम लगाने या आयकर में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

– शमीम खां सुल्तानी, महानगर अध्यक्ष सपा

बजट से छोटे करदाताओं को राहत

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बजट को सराहा, दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर केंद्रित बताया

कार्यालय संवाददाता, बरेली

अमृत विचार: केंद्रीय बजट 2026-27 की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सराहना की और कहा कि यह बजट कर सुधार, निवेश प्रोत्साहन और दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर केंद्रित रहा है।

बजट में छोटे कारोबारियों को मिली टीडीएस छूट, अपील के प्री डिपॉजिट टैक्स में राहत, विदेश में पढ़ाई को जाने वाले बच्चों की फीस जमा करने पर फॉरेन एक्सचेंज के टैक्स (टीसीएस) को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने को अच्छा कदम बताया। वहीं, बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बेस एक्सेप्शन राशि बढ़ाने की उम्मीद पूरी तरह लागू नहीं हुई। बजट में एमएसएमई, स्टार्टअप्स और बायोफार्मा जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी यात्रा, शिक्षा और संपत्ति लेन-देन में कर बोझ कम करना, जुर्माना और न्यूनतम कर में सुधार, निवेश और कर अनुपालन को बढ़ावा देने के संकेत हैं। जुर्माना हटाने से आम करदाता को राहत मिली है। आईटीआर फाइल करने में गलती होने पर वह जुर्माना अदा करके बच सकता है, जेल जाने का डर नहीं रहेगा।

बजट में टीडीएस और टीसीएस नियमों में बदलाव करके कर प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे करदाता आसानी से अनुपालन कर सकें। कैपिटल गेन टैक्स में बेस एक्सेप्शन राशि को सवा लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की संभावना थी, जो पूरी तरह लागू नहीं हुई। यह बजट दीर्घकालिक आर्थिक संतुलन और कर अनुपालन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे करदाताओं और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिलेगा। **– रमेश पांडेय,** कर अधिवक्ता

यह बजट विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगा। बायोफार्मा और तीन नए आयुर्वेदिक मेडिकल हब विकास के नए अवसर खोलेंगे। आयकर में रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा बदलने और एकमुश्त फीस की व्यवस्था से राहत मिलेगी। यह बजट लंबी अवधि के आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास और निवेश पर केंद्रित है, जिससे समृद्धि और जनकल्याण को बल मिलेगा। **– सीए राजेन विद्यार्थी,** मंडलाध्यक्ष रोटरी मंडल

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के लिए कोई बड़ा ऐलान नजर नहीं आया। अधिकांश धन निवेश उत्तर-पूर्वी राज्यों और बिहार की तरफ जाता दिख रहा है। इनकम टैक्स के कई प्रावधानों में पेनल्टी की जगह फीस की व्यवस्था की गई है। ऐसा लगता है कि सरकार का मुख्य फोकस ज्यादा से ज्यादा राजस्व एकत्रित करना है, जबकि बड़े राज्यों की विकास जरूरतों पर अपेक्षित ध्यान कम दिखाई देता है। **– पवन अग्रवाल,** सीए

बजट में सरकार ने विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। डिजिटल इंडिया, तकनीक, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश से दक्षता बढ़ेगी और युवा तैयार होंगे। कुल मिलाकर यह बजट स्थिरता, विकास और समावेशी अर्थव्यवस्था की दिशा में संतुलित कदम लगता है।

– अमित टंडन, सीए

बजट आम जनता के लिए निराशाजनक रहा। आयकर के प्रावधानों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए गए हैं। बेसिक टैक्स छूट और वेतनभोगी वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई वृद्धि नहीं हुई। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20 प्रतिशत से कम करने की उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। कैपिटल गेन एक्सेम्प्शन बढ़ाने की मांग भी अनसुनी रह गई।

– सीए मनोज मंगल, पूर्व अध्यक्ष आईसीएआई

बजट में सीधे कर प्रावधानों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जो करदाताओं के लिए सरलता और राहत लेकर आए हैं। टीसीएस और टीडीएस में छूट, विदेशी यात्रा और शिक्षा पर कर बोझ कम करना, संपत्ति लेन-देन में प्रक्रियात्मक सरलता, मध्यम वर्ग के लिए राहत के रूप में सामने आए हैं। बजट करदाताओं और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए सकारात्मक संदेश देता है।

–सीए अरविंद सिंह, पूर्व अध्यक्ष, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन

बजट स्वागतयोग्य है। जुर्माना और कानूनी कार्रवाई में बदलाव से छोटे करदाताओं का डर कम होगा। विदेशी आय और संपत्ति की घोषणा और अद्यतन रिटर्न प्रावधानों में कड़ाई के बावजूद ईमानदार करदाताओं को राहत मिलेगी। बजट लंबी अवधि में आर्थिक स्थिरता, निवेश प्रोत्साहन और समावेशी विकास को बढ़ाने की दिशा में एक संतुलित कदम है। **–सीए ऋषि पुरी**

अधिवक्ता बोले-संतुलित बजट मगर नौकरीपेशा वर्ग को निराशा मिली

बरेली, अमृत विचार : केंद्रीय बजट पर अधिवक्ताओं ने भी मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने बजट आमजन के लिए बेहतर बताया तो कर्मचारियों के लिए निराशाजनक बताया है। जानते हैं कुछ अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं

सरकार ने कुल मिलाकर बहुत ही संतुलित बजट पेश किया है, जिसमें आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे नौकरी पेशा लोगों को निराशा हाथ लगी, वहीं आम आदमी को राहत दी गयी। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को गति मिलेगी। **– रजत मोहन एडवोकेट,** कनिष्ठ उपाध्यक्ष, बरेली बार एसोसिएशन

बजट बेहतर है, टैक्स स्लैब्स न बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकारी कर्मचारियों को पिछले बजट में जो राहत दी गयी थी, वह बरकरार रहेगी। आम जनता के लिए अच्छा बजट है। **–अजय कुमार अग्रवाल,** एडवोकेट

यह बजट हर वर्ग के लोगों के लिए अच्छा है, हालांकि टैक्स स्लैब्स नहीं बढ़ी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को भले ही लाभ न हो, लेकिन आम जनता को लाभ मिलेगा। हवाई यात्रा पर भी टैक्स में कमी की गयी है। **–रमेश चन्द्र अग्रवाल,** एडवोकेट

एआई बाद में, पहले खाद-बीज और फसलों के सही दाम मिलें

कार्यालय संवाददाता, बरेली

- **किसानों ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक, कहा- उम्मीदें रह गईं अधूरी**
- **किसान नेताओं ने बजट को आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित करार दिया**

अमृत विचार : केंद्रीय बजट को किसान और किसान संगठनों ने निराशाजनक बताया है। उनका कहना कि बजट में स्वास्थ्य और कुछ टेक्नोलॉजी पर फोकस ठीक है, लेकिन खेती-किसानी के मुद्दों को पूरी तरह नजरंदाज किया गया है।

एआई टूल और डिजिटल सलाह की घोषणाओं को लेकर कहा कि उन्हें एआई का मतलब तक ठीक से नहीं पता। हम तो मौसम विभाग की सूचना और अपने अनुभव से खेती करते आए हैं. एआई टूल क्या है, कैसे काम करेगा, गांव में कौन समझाएगा ये भी स्पष्ट करना चाहिए। महंगे कृषि उपकरणों पर भारी टैक्स, फसल बीमा और एमएसपी पर कोई ठोस प्रावधान न होना और कर्ज माफी की अनदेखी ने निराशा और बढ़ा दी है। बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का प्रावधान तक नहीं किया गया।

जबकि किसानों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थीं। किसान नेताओं ने इस बजट को ''आंकड़ों और घोषणाओं का बजट'' करार दिया और साफ तौर पर कहा कि देश के मेहनतकश अन्नदाताओं और ग्रामीणों की अपेक्षाओं को नजरअंदाज करना विकास की गति को कमजोर करेगा।

बजट में खेती और किसानों की बुनियादी जरूरतों जैसे खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर कोई राहत नहीं दी गई। महंगी मशीनरी और बढ़ती लागत किसानों की जेब पर भारी पड़ रही है। फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई ठोस घोषणा न होना किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरना है। सरकार को चाहिए कि वह अन्नदाता और ग्रामीणों को केंद्र में रखकर बजट में वास्तविक राहत और समर्थन की व्यवस्था करे।

–विजय चौहान, प्रगतिशील किसान

कृषि क्षेत्र में बजट पूरी तरह आंकड़ों और घोषणाओं तक सिमट गया है। एआई और डिजिटल टूल की बातें अच्छी हैं, लेकिन हम जमीन पर खेती करते हैं। खाद और बीज की सही कीमत, कर्ज माफी और एमएसपी पर गारंटी किसानों के लिए जरूरी थी। आम किसान इन घोषणाओं से लाभ नहीं उठा पाएगा। सरकार को बजट में गांव और मेहनतकश किसान को प्राथमिकता देनी चाहिए। **– अरुण राठी,** मंडल अध्यक्ष, भाकियू (अराजनैतिक)

बजट में खेती-किसानी के लिए कोई ठोस कदम नहीं दिखा। यह बजट जमीनी सच्चाइयों से दूर, आंकड़ों और घोषणाओं का बजट है, जिसमें देश के अन्नदाता और मेहनतकश वर्ग की अपेक्षाओं की अनदेखी की गई है। सरकार को चाहिए कि वह किसान, मजदूर और ग्रामीण भारत को केंद्र में रखकर अपनी नीतियों और बजटीय प्रावधानों पर पुनर्विचार करे।

– उपदेश सिंह, किसान नेता

हमारे लिए बजट निराशाजनक रहा। महंगी खेती, बढ़ते खर्च और महंगे बीज-खाद ने पहले ही परेशान किया था। एआई टूल और डिजिटल सलाह हमारे लिए समझ से बाहर हैं। अगर सरकार खाद और बीज सस्ते करे, कर्ज माफ करे और एमएसपी की गारंटी दे, तो हम राहत महसूस कर पाएंगे। आम किसान को असली मदद वही है, जो सीधे खेत और जेब पर असर डाले।

–जागन लाल मौर्य, किसान

'ड्यूटी फ्री' आयातित वस्तुएं लाने की सीमा 75 हजार रुपये हुई

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने भारत में ''ड्यूटी फ्री'' आयातित सामान लाने की सीमा रविवार को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी। रविवार को अधिसूचित सामान नियम, 2026 के तहत भारत में भूमि मार्ग के अलावा किसी भी अन्य मार्ग से आने वाले भारतीय नागरिकों या भारतीय मूल के पर्यटकों को 75,000 रुपये तक का ''ड्यूटी फ्री'' सामान लाने की अनुमति होगी। नये नियम दो फरवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी हो जाएंगे और एक दशक पुराने सामान संबंधी नियम की जगह लेंगे। नये नियमों के तहत भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों (शिशु को छोड़कर) को 25,000 रुपये तक के मूल्य का ''ड्यूटी फ्री'' सामान लाने की इजाजत होगी। पहले यह सीमा नियम के तहत 15,000 रुपये थी। सामान नियम, 2026 के मुताबिक, अगर भारतीय मूल का कोई निवासी या पर्यटक एक साल से अधिक समय से विदेश में रह रहा है और भारत लौटता है, तो उसे 40 ग्राम तक का ''ड्यूटी फ्री'' आभूषण लाने की छूट होगी, यह आभूषण किसी महिला यात्री द्वारा लाया जाए। नियम के अनुसार, अगर महिला यात्री के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वैध सामान में आभूषण लाता है, तो यह सीमा 20 ग्राम होगी।

विकसित भारत के लक्ष्य पर आधारित है आम बजट

बजट विकसित भारत के लक्ष्य पर केंद्रित, युवा-शक्ति, आत्मनिर्भरता और सुधारों पर आधारित है। आर्थिक वृद्धि को तेज करने, रोजगार सृजन और तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया है। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए मध्यम वर्ग को कर राहत और आसान टैक्स व्यवस्था की गयी है। शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं के रोजगार पर विशेष फोकस किया गया है। पूर्वी भारत, टियर-2 व टियर-3 शहरों और पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

– छत्रपाल गंगवार, सांसद भाजपा

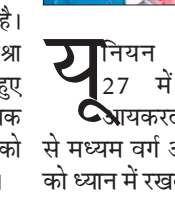

केंद्रीय बजट हर वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति की राह पर है। बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये बजट मददगार साबित होगा। **–सोमपाल शर्मा,** जिलाध्यक्ष बरेली भाजपा

आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की दिशा में सशक्त कदम है। 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित बजट पूरे देश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट केवल आंकड़ों और योजनाओं का प्रस्तुतिकरण नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत के संकल्प को साकार करने का माध्यम है। **–अधीर सक्सेना,** महानगर अध्यक्ष भाजपा

बजट में आज नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग को निराशा मिली है उन्हें आयकर में छूट की उम्मीद थी। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पांच मेडिकल हब बनाए जाने से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, रेल कॉरिडोर बनाने से रेल यातायात में सुधार होगा, साथ ही तीव्रगामी रेल सेवा उपलब्ध होगी, अगर युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला बजट में प्रावधान होता तो और अच्छा रहता।

–तनवीर अहमद कादरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य

केंद्रीय बजट की सराहना की

फतेहगंज पूर्वी, अमृत विचार : केंद्र सरकार के द्वारा आज पेश किए गए बजट की लोगों ने सराहना की तथा बजट को जनता के हित में बताया। वही सपा कार्यकर्ताओं ने बजट को जनता के साथ एक धोखा बताया। नगर पंचायत कार्यालय पर आज लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट का लाइव प्रसारण देखा। बजट पेश होने के बाद भाजपा नेता पवन राज मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह जनता के हित में है तथा सराहनीय है। भाजपा नेता सुधीर सिंह ब ऋषभ मिश्रा ने भी बजट की सराहना करते हुए प्रशंसा की। वहीं सपा नेता रामसेवक शर्मा बुधपाल सिंह यादव ने बजट को जनता के साथ एक धोखा बताया।

इनकम टैक्स में छूट मिलती तो खुशी होती

फरीदपुर। डायट प्रवक्ता श्रीकांत मिश्र ने कहा कि बजट में हर शहर में 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, प्रत्येक शहर में 4000 इलेक्ट्रिक बस, आदि से आम आदमी का जीवन आसान होगा तथा सुविधाएँ बढ़ेंगी। महिलाओं के लिए शी मार्ट का निर्माण, लखनऊ में एआई सिटी का विकास प्रदेश के विकास में सहायक होगा।

त्वरित टिप्पणी | **मध्यम वर्ग की आय, बचत और उपभोग क्षमता को संतुलित बनाए रखने का प्रयास**

मध्यम वर्ग के लिए स्थिरता के साथ राहत का बजट

आम बजट 2026-27

यूनियन बजट 2026-27 में सरकार द्वारा आयकरदाताओं, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग को ध्यान में रखते हुए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। बजट का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, अनुपालन को आसान करना तथा मध्यम आय वर्ग की वास्तविक आय को संरक्षित रखना प्रतीत होता है। सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की गई। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी हो जाएगा।

आयकर के संदर्भ में बजट में कोई बड़ा या चौंकाने वाला परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि पहले से लागू नई कर व्यवस्था को ही बरकरार रखा गया है। यद्यपि नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब अपेक्षाकृत सरल है और धारा 87A के तहत मिलने वाली छूट के कारण लगभग 12 लाख तक की आय पर कर लगभग शून्य है। इससे मध्यम वर्ग के उन करदाताओं को सीधा लाभ मिलता है, जिनकी आय सीमित है, लेकिन महंगाई के कारण खर्चों में वृद्धि होने से बचत प्रभावित हुई है।

बजट में टैक्स रिटर्न फाइलिंग और टीडीएस व टीसीएस से जुड़े नियमों को अधिक पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) पर जोर दिया गया है, जिससे करदाताओं को अनावश्यक प्रक्रियात्मक परेशानियों से बचाया जा सके।

मध्यम वर्ग के लिए यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से महंगाई को नियंत्रित रखने का प्रयास किया है। बजट में आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में छूट एवं अन्य अप्रत्यक्ष करों में बड़े बदलाव से उपभोक्ताओं के दैनिक खर्चों अथवा अतिरिक्त बोझ डालने से बचाने का प्रयास किया गया है। साथ ही निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से कैंसर सहित गंभीर रोगों पीड़ित मरीजों के लिए 17 दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट तथा 7 और दुर्लभ रोगों को शुल्क-मुक्त आयात योजना में शामिल किया जाने का प्रस्ताव प्रशंसनीय है।

इसके अतिरिक्त, छोटे करदाताओं के लिए निल डिडक्शन सर्टिफिकेट जैसी व्यवस्थाएं टीडीएस की अनावश्यक कटौती को रोकने में सहायक होंगी। यह उन लोगों के लिए विशेष राहत है जिनकी आय सीमित है, लेकिन तकनीकी कारणों से पहले टैक्स कट जाता था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने 15% की बढ़ोतरी कर रक्षा बजट को को 6.81 लाख करोड़ से 7.85 लाख करोड़ कर दिया है जो कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक शस्त्रों के निर्माण विकास हेतु अति आवश्यक है।

कुल मिलाकर, यूनियन बजट 2026-27 आयकरदाताओं और मध्यम वर्ग के लिए ''स्थिरता के साथ राहत'' का बजट कहा जा सकता है। सरकार का यह बजट संकेत देता है कि मध्यम वर्ग को आर्थिक विकास की धुरी मानते हुए उसकी आय, बचत और उपभोग क्षमता को संतुलित बनाए रखने का प्रयास किया गया है और बजट में हर क्षेत्र के हितधारकों का ध्यान रखा गया है।

- डॉ. बृजवास कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, बरेली कॉलेज

संपत्ति से बेदखल करने पर पिता और बहन को पीटा, रिपोर्ट

बरेली, अमृत विचार : संपत्ति से बेदखल करने पर युवक ने पत्नी के साथ मिलकर पिता और बहन के साथ मारपीट की। एसएसपी के आदेश पर बारादरी पुलिस ने दंपती समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

बारादरी थाना क्षेत्र के जगतपुर निवासी बुजुर्ग मोहम्मद कमर ने बताया कि उन्होंने बेटे अनवार और उसकी पत्नी आसमा को गलत कामों की वजह से अक्टूबर 2025 में अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। बेटा और बहू रंजिश मानने लगे। आरोप है कि 28 जनवरी को बेटे, बहू और उसके ससुराली लाठी डंडे लेकर घर में घुस आए। इन लोगों ने उसकी बेटी शबीना के साथ मारपीट की। जान से मारने की नीयत से उनका भी गमछे से गला दबाया। आरोपियों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। शोर शराबा होने पर पड़ोसियों ने किसी तरह से उनकी जान बचाई। पुलिस ने अनवार, आसमा बी, फुरकान उल्ला, गुड्डू, गुफरान, निजाम और इल्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।